'अगर भारत, ब्राज़ील और चीन ने रुस से तेल खरीदना जारी रखा तो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे'

ट्रंप के बाद अब नाटो के महासचिव ने भी खुली धमकी दी

- नाटो चीफ ने पत्रकारों से कहा कि, पुतिन को फोन कर शांति वार्ता में गंभीर होने को कहें नहीं तो भारत, चीन और ब्राज़ील को इसकी उलटी मार झेलनी होगी।

वॉशिंगटन, 16 जुलाई। नाटो के महासचिव मार्क रुटे ने बुधवार, 15 जुलाई को चेतावनी दी कि अगर ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ अपना व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर भी आर्थिक प्रतिबंध (सेकेंडरी सैंक्शंस के रूप में) लगाए जा सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही यूक्रेन के लिए नाटो के माध्यम से नए हथियारों की घोषणा की थी और साथ में 50 दिनों में शांति समझौता नहीं होने की स्थिति में रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत के सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। ट्रंप के इस ऐलान के अगले दिन नाटो महासचिव अमेरिकी कांग्रेस में सीनेटरों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने ब्राजील, चीन और भारत जैसे देशों को यह धमकी दी।

रुटे ने सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से कहा, इन तीन देशों को मेरा परामर्श, विशेष रूप से यह है कि यदि आप अभी बीजिंग में रहते हैं, या दिल्ली में हैं, या आप ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो आप शायद इस पर गौर करना चाहेंगे, क्योंकि यह आपको बहुत भारी पड़ सकता है।

रुटे ने कहा, "तो कृपया व्लादिमीर पुतिन को फोन करें और उन्हें बताएं कि उन्हें शांति वार्ता के बारे में गंभीर होना होगा, नहीं तो इसकी उलटी मार ब्राजील, भारत और चीन को बड़े पैमाने पर झेलनी होगी।"

रिपब्लिकन अमेरिकी सीनेटर थॉम टिलिस ने इन कदमों की घोषणा के लिए ट्रंप की तारीफ की, लेकिन कहा कि 50 दिन की देरी उन्हें "चिंतित" करती है।

उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता है कि पुतिन युद्ध जीतने के लिए 50 दिनों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे, या हत्या करने और संभावित रूप से बातचीत के आधार के रूप में अधिक जमीन हथियाने के बाद शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे।

उन्होंने कहा, "इसलिए हमें आज यूक्रेन की वर्तमान स्थिति को देखना चाहिए और कहना चाहिए, चाहे आप अगले 50 दिनों में कुछ भी करें, आपका कोई फायदा होने नहीं जा रहा है।"

स्वर्ण मंदिर को लगातार तीसरे दिन बम की धमकी

अमृतसर, 16 जुलाई। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये लगातार तीसरा दिन है, जब इस तरह की धमकी फिर दी गई है।

इस धमकी को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। कमेटी ने पुलिस से पूरे मामले की जांच करके धमकी देने वालों पर तुरंत एक्शन लिए जाने की मांग की है। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि दरबार साहिब के संबंध में लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। बीते लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि समूची मानवता के आस्था के केन्द्र दरबार साहिब पर समय-समय पर हमले भी हुए और इसे नुकसान भी पहुंचाया जाता रहा है। 1984 में भी बहुत बड़ा नुकसान किया गया था। 14 जुलाई से लगातार धमकियां मिल रही हैं।

- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुलिस में शिकायत कर जल्द ही एक्शन लेने की मांग की है।

चाहो तो साथ आ जाओ, फड़नवीस ने उद्धव ठाकरे को दिया ऑफर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के इस ऑफर से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है

- फड़नवीस ने कहा कि महायुति गठबंधन 2029 तक तो सत्ता में ही रहेगा।

पुणे, 16 जुलाई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2029 तक भाजपा या उनका गठबंधन विपक्ष में जाने वाला नहीं है। उन्होंने शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे को इशारों में सत्ता पक्ष में शामिल होने का ऑफर भी दिया। यह बयान उस वक्त आया है जब बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव नजदीक हैं और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।

भाजपा की यह रणनीति बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना (उद्धव गुट) की स्थिति को कमजोर करने का प्रयास भी हो सकती है।

विधान परिषद सत्र के दौरान बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कम से कम 2029 तक हमारे विपक्ष में जाने की कोई संभावना नहीं है। भरी विधान परिषद में उन्होंने कि उद्धव जी चाहें तो इस तरफ आने के बारे में सोच सकते हैं।

कम से कम 2029 तक तो हम विपक्ष में नहीं आएंगे। इस बयान के बाद अब एक और संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह विचार एक अलग तरीके से किया जा सकता है, जिससे यह बयान और ज्यादा सियासी मायनों से भर गया है।

पिछली बार बीएमसी में शिवसेना और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर थी। बीएमसी फिलहाल उद्धव ठाकरे गुट के नियंत्रण में है। भाजपा चाहती है कि इस बार वह बीएमसी पर कब्जा करे और इसके लिए वह सभी राजनीतिक समीकरण साधने में जुट गई है।

एसीबी केस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्रमोन्नत करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया था। अभियुक्त कनिष्ठ लेखाकार शीशराम ने मान्यता से पहले निरीक्षण करने को कहा। बाद में 3 मई, 2008 को फोन कर 8 मई को समस्त रिकॉर्ड एवं खर्चे के नाम पर छः हजार रुपए लेकर आने को कहा। एसीबी ने 12 मई, 2008 को शीशराम को पांच हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

दादिया में गुरुवार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संबंध में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को आमजन के लिए जरूरी सुविधाएं एवं बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया।

कार्यक्रम की तैयारी के लिए जहां राज्य सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, वहीं, उसके साथ भाजपा की ओर से भी तैयारी की जा रही है। प्रशासन द्वारा दादिया में बड़ा सभा स्थल तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश के करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। इसके लिए दादिया में रिंग रोड पर स्थित सभा स्थल में तीन डोम बनाए गए हैं। इन तीनों डोम में लगभग एक लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सहकार उत्सव व रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग-अलग स्टॉल लगाई जाएंगी। सभा स्थल पर एक मंच तैयार किया गया है और तीन डोम, पार्किंग एवं सारी व्यवस्थाएं की गई है।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, सांसद मदन राठौड़, सीपी जोशी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित, संबंधित उच्चाधिकारी मुख्यमंत्री के साथ थे।

हाईकोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रार्थी के पक्ष में स्टे दे रखा था। वहीं, शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ 2022 में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस एफआईआर पर कार्रवाई करते हुए 28 मई 2025 को प्रार्थी को अचानक ही अवैध रुप से गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से पहले पुलिस ने न तो उसे कोई नोटिस दिया और न ही गिरफ्तारी का कोई कारण बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी को नोटिस देना और इसका कारण लिखित में बताना जरूरी है। इस प्रकार प्रार्थी के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ है।

आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने के बाद जश्न मनाया था

एक चश्मदीद गवाह ने एनआईए को दिए बयान में कहा कि आतंकियों ने हवा में गोलियां दागी थीं

- एनआईए, जो पहलगाम हमले की जांच कर रही है, ने उक्त गवाह को "स्टार प्रोटैक्टेड" श्रेणी में रखा है।
- गवाह ने बताया कि आतंकी तीन ही थे, दो तो उनके स्थानीय मददगार थे, गवाह ने उन दोनों की पहचान की है।

श्रीनगर, 16 जुलाई। पहलगाम बैसरन में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या का आतंकियों ने जश्न मनाते हुए हवा में गोलियां भी दागी थीं। इसके बाद वे वहां से अपने किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ निकल गए।

यह जानकारी इस जघन्य कांड की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से चिन्हित किए गए एक स्थानीय गवाह से हासिल की है। इसी गवाह ने आतंकियों के पकड़े गए दो मददगारों परवेज अहमद जोथड़ और बशीर अहमद जोथड़ को वहीं पास में एक पहाड़ी पर कुछ सामान के साथ देखा था।

आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने, जिनकी संख्या पहले पांच तक बताई जा रही थी तथा अब तीन बताई जाती है, ने बैसरन पहलगाम में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय घोड़ेवाले की हत्या की थी। इस जघन्य कांड को अंजाम देने वाले आतंकी अभी तक सुरक्षाबलों की पकड़ से दूर हैं।

एनआइए ने अभी तक इस मामले में उनके दो स्थानीय मददगारों परवेज अहमद जोथड़ और बशीर अहमद जोथड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा एनआइए ने एक स्थानीय नागरिक का भी पता लगाया है, जिसे आतंकियों ने बैसरन से निकलते हुए रोका था।

एनआइए से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस मामले में अभी तक जिन गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, उनमें सबसे अहम यही एक स्थानीय गवाह है। एनआइए ने इसे जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से चिन्हित किया है। पूछताछ में इसने बताया कि मौत का नंगा नाच खेलने के बाद आतंकी जब बैसरन से निकल रहे थे तो वहीं रास्ते में उसका सामना आतंकियों से हुआ था। आतंकी तीन ही थे।

उन्होंने पहले उसे भी पर्यटक समझा, लेकिन जब उसने कहा कि वह पर्यटक नहीं, स्थानीय नागरिक है, तो पहले उन्होंने उससे उसका नाम पूछा और फिर उसे कलमा पढ़ ने को कहा। उसने अपना नाम बताया और कलमा भी पढ़ ा। इससे आतंकियों को उसके मुस्लिम व स्थानीय कश्मीरी होने का यकीन हो गया। उन्होंने उसे छोड़ दिया और फिर वहीं उसी समय हवा में ऐसे गोलियां दागी, जैसे वे किसी जीत का जश्न मना रहे हों।

उक्त गवाह के अनुसार, उसने वहीं कुछ ही दूरी पर परवेज और बशीर को भी खड़े देखा था। उनके पास कोई सामान था। वे दोनों पहले से ही आतंकियों का इंतजार कर रहे थे। उक्त गवाह के अनुसार, वह स्थानीय होने के कारण इन दोनों को अच्छी तरह से पहचानता है। उसने हमलावर आतंकियों में सुलेमान उर्फ सुलेमानी उर्फ हाशिम के शामिल होने की भी पुष्टि की है।

एनआइए ने उक्त गवाह को स्टार प्रोटेक्टिड की श्रेणी में रखा है। उसने जिस जगह आतंकियों के साथ आमना, सामना होने की जानकारी दी है, एनआइए ने वहां से कुछ चले हुए कारतूस भी बरामद किए हैं।

कांग्रेस शासन में लगे सरकारी वकीलों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नियुक्त हुए थे। याचिकाकर्ताओं के कार्यकाल को 5 अगस्त, 2024 को, नए वकीलों की नियुक्ति नहीं होने के आधार पर, बढ़ाया गया था। फिर गत 3 जुलाई को उन्हें इस पद से रिलीव कर दिया गया और उनके पद का कार्यभार दूसरे सरकारी वकीलों को दे दिया। याचिका में कहा गया कि पांच अगस्त के आदेश के बाद से अब तक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। याचिकाकर्ताओं के स्थान पर नई नियुक्ति नहीं की गई और दूसरे सरकारी वकीलों को ही अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने उन्हें राजनीतिक कारणों के चलते मनमानी से रिलीव किया है। ऐसे में रिलीव करने के आदेश को रद्द किया जाए।

मामले की सुनवाई करते हुए, एकलपीठ ने रिलीव आदेशों की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

'न्यायिक सेवा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि इस अनिवार्यता से दिव्यांगों एवं ट्रांसजेन्डर उम्मीदवार भी नुकसान में रहेंगे, क्योंकि उन्हें अदालतों तथा लॉ चैम्बर्स में समावेशी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी प्रभावित करेगी।

याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर भी सवाल उठाए गए हैं कि वह, लिटिगेशन के दौरान, छात्रों के हितों की रक्षा में विफल रही है। इसमें कहा गया है कि बीसीआई न तो उच्च फीस, न ही अनियमित कानून कॉलेजों, और न ही वकीलों को समय पर पंजीकरण देने जैसी समस्याओं का समाधान कर सकी है।

कुल मिलाकर, बीसीआई की नियामक निष्क्रियता, खराब जवाबदेही तथा पारदर्शिता के अभाव के कारण न केवल कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है, बल्कि न्यायिक संकट में भी इसका योगदान रहा है, जिसका बोझ अभ्यर्थियों, खासतौर से वंचित वर्ग तथा कानून-संबंधी पृष्ठभूमि से रहित अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। अगर मुद्दा क्षमता एवं तैयारी का है, तो इसका मूल कारण केवल वकालत के अनुभव की कमी में नहीं, बल्कि संबंधित सिस्टम की असफलता में निहित है, क्योंकि बीसीआई इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी है तथा इस प्रकरण में बीसीआई की खामोशी और भी ज्यादा चिंताजनक है। पुनर्विचार याचिका में मांग की गई है कि मई 2025 के फैसले पर रोक लगाई जाये, इस नियम को 2026 बैच से लागू किया जाये, प्रभावित होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाये तथा इस नियम के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ आयोग का गठन किया जाये। याचिका में अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि बीसीआई को नामांकन और कॉलेज मान्यता प्रणाली में सुधार के निर्देश दिये जाये। इससे पहले, अधिवक्ता चंद्र सेन यादव ने भी एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस नियम (तीन वर्ष की अनिवार्य वकालत) को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आलोचना का विषय बन गया है, विशेषकर इस कारण कि यह महिलाओं को न्यायिक सेवा की ओर बढ़ने से रोक सकता है या उनकी न्यायिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा होने में देरी कर सकता है।

चंद्रबाबू...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर्दे के पीछे, 2027 के संभावित राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए गंभीर पुनर्विचार की प्रक्रिया चल रही है।

भारतीय सेना ने आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया

परीक्षण लद्दाख में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर किया गया

- रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में भी शानदार प्रदर्शन किया था।

नई दिल्ली, 16 जुलाई। भारतीय सेना ने बुधवार को स्वदेशी रूप से विकसित किए गए आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण लद्दाख क्षेत्र में 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर किया गया। परीक्षण सेना ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ, जिन्होंने इस प्रणाली को विकसित किया है।

परीक्षण के दौरान सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने बहुत तेज गति से उड़ रहे हवाई लक्ष्यों पर सीधा प्रहार किया। यह परीक्षण बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया गया।आकाश प्राइम सिस्टम अब भारतीय सेना की हवाई सुरक्षा की तीसरी और चौथी यूनिट (रेजिमेंट) का हिस्सा बनेगा। इसका मतलब है कि अब यह नई प्रणाली सेना की और दो टुकड़ियों में शामिल की जाएगी ताकि दुश्मन के हवाई हमलों से और बेहतर तरीके से रक्षा की जा सके।

रक्षा अधिकारियों के अनुसार, इस प्रणाली ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उस समय पाकिस्तान की सेना द्वारा चीनी विमानों और तुर्किये के ड्रोन से किए गए हवाई हमलों को इस प्रणाली ने सफलतापूर्वक नाकाम किया था। आकाश प्राइम सिस्टम भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की बड़ी कोशिश का हिस्सा है, खासकर वायु सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्र में।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा कि इस मामले में फिल्म डायरेक्टर के साथ कन्हैयालाल के बेटे को भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस पर कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस मामले में संबंधित कमीशन और एसपी इसका आंकलन करें।

इंडिगो फ्लाइट की मुंबई में इमरजैंसी लैंडिंग

नई दिल्ली, 16 जुलाई। दिल्ली से गोवा जा रही इंडिगो फ्लाइट को मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि विमान का एक इंजन फेल हो गया था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

इंडिगो प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली से मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, गोवा के लिए उड़ान भरते समय उड़ान संख्या 6ई 6271 में तकनीकी खराबी का पता चला। प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, विमान को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया।

- दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट का एक इंजन फेल हो गया था।

सूत्रों ने बताया कि एयरबस ए320एनईओ से संचालित इस उड़ान की रात 9.52 बजे आपातकालीन लैंडिंग हुई। उड़ान में सवार लोगों की संख्या का तुरंत पता नहीं चल सका है।

इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि विमान यात्रा पूरी करने के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई है।

भारत को "फिफ्थ जैनरेशन"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हेलीकॉप्टर 2015 में अमेरिका और बोइंग के साथ हुए समझौते के तहत मिले थे। इस बार जो छह अपाचे मिल रहे हैं, वे 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान हुए 600 मिलियन डॉलर के सौदे का हिस्सा हैं, और इन्हें भारतीय सेना को दिया जाएगा।

अपाचे के साथ-साथ, भारत के घरेलू फाइटर जेट प्रोग्राम एएमसीए को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला है। सरकार ने इसके "एग्ज़ीक्युटिव मॉडल" को मंजूरी दे दी है। यह फाइटर जेट पूरी तरह से भारत में बनेगा और 5वीं पीढ़ी का स्टैल्थ फाइटर होगा, जिसमें गहराई तक घुसकर हमला करने की क्षमता होगी। यह भारत को अमेरिका, रुस व चीन के समकक्ष पहुंचा देगा, जिनके पास उनके देश में ही बने पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं।

इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) कर रही हैं, और इसमें एचएएल (हिन्दुस्तान एटोनॉटिकल लिमिटेड) भी सहयोग कर रहा है। यह दो इंजन वाला मल्टी-रोल फाइटर होगा, जिसमें स्टैल्थ, सुपरक्रूज़, इंटरनल वेपन बे, और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जैसी खूबियाँ होंगी। इसे भविष्य में अपग्रेड करने के लिए मॉड्यूलर डिज़ाइन में बनाया जाएगा, जिसमें बिना पायलट के उड़ान की क्षमता भी शामिल हो सकेगी।

सरकारी मंजूरी के बाद, अब दो टैक्नॉलजी डैमोंस्ट्रेटर और पांच लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन यूनिट बनाए जाएंगे। इसका पहला उडान परीक्षण अभी वर्षों दूर है और माना जा रहा है यह 2030 के आसपास काम करने लगेगा। लेकिन यह कदम भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' योजना के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत इशारा है। इस समय भारतीय वायुसेना एसयू-30 एमकेएल और राफेल जैसे चौथी पीढ़ी के विमानों पर निर्भर है। जब तक एएमसीए पूरी तरह तैयार नहीं होता, भारत 5वीं पीढ़ी के कुछ विमान बाहर से खरीदना जारी रख सकता है। लेकिन डिज़ाइन, निर्माण और रक्षा निर्यात क्षमता की दिशा में एएमसीए भारत की दीर्घकालिक सोच है।

अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती और एएमसीए प्रोजेक्ट की मंजूरी भारत की दोहरी रणनीति को दर्शाती है। एक ओर, अभी के लिए क्षमता की कमी को पूरा करना, और दूसरी ओर, भविष्य के लिए स्वदेशी रक्षा ढांचा खड़ा करना। एक तरफ अपाचे जांचा परखा "अजेय उड़न दुर्ग" है, और दूसरी ओर एएमसीए तकनीकी संप्रभुता की एक साहसी योजना है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908